DR. KARAN SINGH: Sir, it is not a question of new requests. These projects have been on the anvil for many years, for decades. In fact Salal project was planned in my father's time. It is not a new request that is required. These are ongoing projects. Perhaps, the Minister may enquire from the concerned Ministry and let us know.

SHRI HARIN PATHAK: Sir, whatever the pending projects are there, we will pursue them.

आतंकवादी गुट द्वारा आतंकवादी हमलों की धमकी

*383. **श्रीमती सविता शारदा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''लश्कर-ए-तैय्यबा'' नामक आतंकवादी गुट ने भारत में बड़े पैमाने पर नये सिरे से अनेक आतंकवादी हमले करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धमकी का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) ''लश्कर-ए-तैय्यबा'' और जैश-ए-मोहम्मद जैसे अन्य पाक इस्लामिक ग्रुप जम्मू और कश्मीर में व्यक्ति विशेषों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों को निशाना बना रहे हैं और इन्हाने हाल के वर्षों में भारत के अन्दरूनी भागों में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है।

(ग) आतंकवाद के खतरे से मुकाबला करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित कार्रवाईयों का प्रबोधन करना, राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण करना और सीमापार अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना शामिल है।

केन्द्र सरकार आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न खतरे की आशंका के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को सचेत करती रहती है।

Threatening of terrorist strikes by terrorist outfit

†*383. SHRIMATI SAVITA SHARDA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether terrorist outfit 'Lashkar-e-Taiba' has threatened to carry out a fresh series of terrorist strikes on a large scale in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps Government have taken to meet the threat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) 'Lashkar-e-Toiba' and other Pak Islamic groups such as Jaish-e-Mohammad have been targeting individuals, installations and institutions in Jammu and Kashmir and have extended their activities to the Indian hinterland in recent years.

(c) In order to tackle the menace of terrorism, the Central Government has adopted a multi-pronged approach which includes strengthening of the borders, galvanizing the intelligence machinery, monitoring of well coordinated intelligence based operations, modernization of State Police Forces and CPMFs and strengthening of international/bilateral cooperation to counter cross border crime and terrorism.

The Central Government has been sensitizing the State Governments from time to time about the threat perception generated due to terrorist groups activities.

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आतंकवाद पहले की अपेक्षा बढ़ा है। आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैय्यबा ने भारत में बड़ी संख्या में आत्मघाती हमलों की नई श्रृंखला शुरू करने और प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री तथा देश के अन्य नेताओं की हत्या की धमकी दी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि सरकार द्वारा अनेक बार आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित किये जाने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी इन आतंकवादी

†Original notice of the question was received in Hindi.

गतिविधियों में कमी नहीं आई बल्कि आतंकवादी घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है? अभी कश्मीर में जो 24 कश्मीरी पंडित मारे गए और मुम्बई में जो बम विस्फोट हुए, उसके बारे में भी मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ।

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, यह सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारे पड़ौसी पाकिस्तान में स्थित जो आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने पिछले पन्द्रह-बीस साल से हमारे देश के खिलाफ छद्म-युद्ध की शुरूआत कर रखी है। उसके अंतर्गत वे लोग इस देश में घुसपैठ करके आतंकवादी वारदातें करते रहते हैं और वे यह भी देखते रहते हैं कि अगर कभी पिछले कुछ वर्षों में ऐसी वारदातें कम हुई हैं तो वे लोग दूसरे वर्षों में उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। इससे निपटने के लिए सरकार ने बार-बार सिचुएशन को रिव्यू करके एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सीमा को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित कार्रवाईयों का प्रबोधन करना, राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण करना और सीमापार अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना शामिल है।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मंत्री जी ने बहुत सारी बातों की जानकारी दी है लेकिन मेरी जानकारी है कि कई बार राज्य सरकारों की वहां तक पहुंच नहीं हो पाती है, जैसे अभी गुजरात में हुआ और सब जगह हो रहा है। मैं अभी मुम्बई में थी, वहां विले पार्ले में घटना घटी, तो कई बार राज्य सरकारों के पास इतनी सहायता नहीं हो पाती है। मैं मंत्री महादय से यह पूछना चाहती हूं कि गत तीन वर्षों में क्रमश: कितनी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, उनमें कितने व्यक्ति मारे गए और क्या सरकार द्वारा आतंकवादियों द्वारा दी गई धमकी का सामना करने के लिए की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप आतंकवादी गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है? यदि है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, माननीया सदस्या ने तिछले तीन वर्षों के बारे में पूछा है। इस बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर डिटेल में जाया जाए तो 2000 में नम्बर आफ इंसिडेंट्स हुए 3074, 2001 में इंसिडेंट्स हुए 4022, 2002 में इंसिडेंट्स हुए 4038। 2000 में नागरिक मारे गए 847, 2001 में 996, 2002 में 1008। सुरक्षा बल के जवान मारे गए 2000 में 397, 2001 में 536 और 2002 में 453। टेरोरिस्ट्स इन्कलूडिंग फारेन टेरोरिस्टस मारे गए 2000 में 1520, 2001 में 2020 और 2002 में मारे गए 1707। इन सारी घटनाओं में अगर हम फिगर देखते हैं तो यह पता चलता है कि वह मोटे तौर पर स्टेबल रहती है। सरकार की यह कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से इन घटनाओं को रोका जाए। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारा जो आसूचना तंत्र है, उसके कारण हम राज्यों को समय-समय पर इस बात से अवगत कराते रहते हैं कि इस राज्य में और विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, यू०पी० तथा दिल्ली, इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। जैसे इन्होंने अभी मुम्बई की ट्रेन दुर्घटना का उल्लेख किया. .(व्यवधान)...

श्रीमती सविता शारदा: सर, मैं जानना चाहती हूं कि कुल कितने मारे गए?

श्री सभापति: बीच में मत बोलिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री हरिन पाठक: उसके लिए मैंने सारे फिगर बता दिए हैं। हर साल का मैंने आपको बता दिया है, आपको चाहिए तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं।

श्रीमती सविता शारदा: नहीं, आप उन्हें टेबल पर रख दीजिएगा।

श्री हरिन पाठक: मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सूचना के कारण ही मुम्बई में उस घटना के बाद तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लश्करे तैय्यबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी गुटों का संस्थापक कौन है? दूसरे, इन्हें अपने उत्तर में बताया है कि केन्द्र सरकार आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्करे तैय्यबा के संस्थापकों को जो इस देश के तत्कालीन विदेश मंत्री बाइज्जत छोड़ने के लिए गए थे, इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस प्रकार से आतंकवादी ग्रुपों को समाप्त करने का आपका दृष्टिकोण है? मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट करें कि ऐसे आतंकवादी ग्रुपों के जो संस्थापक हैं, उनको छोड़ने की गलती दोबारा नहीं की जाएगी, क्या सरकार का यह इरादा है?

श्री हरिन पाठक: महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। वह एक राजनीतिक समस्या थी।

श्री मूल चन्द मीणा: इसमें प्रश्न से अलग क्या है? आतंकवादी गुट के बारे में ही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बताइए कि इन ग्रुपों के संस्थापकों को छोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य था?

श्री सभापति: यह बहुत बार डिस्कस हो चुका है।

श्री हरिन पाठक: महोदय, यह प्रश्न बहुत बार डिस्कस हो चुका है।

श्री मूल चन्द मीणा: हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उत्तर ही तो बताना है, आप बता दीजिए। डिस्कशन तो कई बार हुआ है। सरकार का ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने का कोई इरादा है?

श्री हरिन पाठक: सभापति महोदय, सरकार का रवैया बहुत स्पष्ट है। किसी भी कीमत पर हमारे देश पर आतंकवादी हमला करने वाले, देश की एकता व अखंडता को तोड़ने वाले तत्वों के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं।

श्री सभापति: बहुत बढ़िया। डा॰ कुमकुम राय।

श्री मूल चन्द मीणा: क्या कार्रवाई की है? देश के तत्कालीन विदेश मंत्री उनको बाइज्जत छोड़ने गए थे।

डा॰ कुमकुम राय: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में आसूचना तंत्र को सक्रिय करने और सीमा को सुदृढ़ करने के बारे में बताया है। सीमा को सुदृढ़ करने के बारे में मैं आपके माध्यम मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि बिहार से जो नेपाल की सीमाएं हैं, ये खुली सीमाएं हैं और बंगलादेश से भी लोग आराम से आ जाते हैं। जब भी किसी कांड का उद्‌भेदन होता है तो यह पता लगता है कि लोग आराम से बंगलादेश चले जाते हैं और बंगलादेश से नेपाल, नेपाल से बिहार और उसके बाद वे देश के विभिन्न हिस्सों में आकर, आतंकवादी गतिविधियां करके आराम से निकल जाते हैं। तो जहां तक सीमा को सुदृढ़ करने का प्रश्न है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या बिहार में नेपाल से लगी हुई जो सीमाएं हैं, उनको सील किया जाएगा और वहां पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा?

इसी से जुड़ा हुआ मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि चूंकि जम्मू-कश्मीर में निरंतर ये वारदातें होती हैं और इन वारदातों की ज्यादातर शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं, उनका जीवन इस दुख-दर्द का ज्यादा शिकार होता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार महिलाओं को भी अस्त्र-शस्त्र का प्रशिक्षण देकर उन्हें ग्राम रक्षा समिति में शामिल करके आतंकवादियों से लोहा लेने का प्रशिक्षण देगी तथा हमारी सीमाओं के नज़दीक, हमारे बगल के देश में, जो प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, उन आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करने का सरकार का कोई विचार है या नहीं?

श्री सभापति: यह महिलाओं के सशक्तीकरण का मामला है।

श्री हरिन पाठक: महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं इसका स्वागत करता हूं। सीमांत इलाकों में जो महिलाएं रहती हैं, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। हमारा एक संगठन है स्पेशल सर्विसेज़ ब्यूरो, जो इस काम में लगा हुआ है। जो राज्य सीमांत क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन राज्य सरकारों को हम पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी राशि देते हैं और उस राशि के जरिए वे अपनी सीमाओं की रक्षा करने में कामयाब होती हैं।

डा॰ कुमकुम राय: बिहार से जो खुली हुई सीमाएं नेपाल की ओर जाती हैं, उस विषय में भी बता दीजिए,...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, अब मत बोलिए आप।

DR. MANMOHAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, hon. Minister has referred to the ongoing process of modernisation of the Central Para-military Forces as part of the process of dealing with the terrorist activities. Sir, through you, I wish to draw the attention of the hon. Minister to the thought-provoking book that has been authored by one of the very distinguished Members of this House, Gen. Shankar Roy Chowdhury, in which, I think, serious doubts have been cast about the ability of the Central Para-military Forces to cope with the challenges that we face in dealing with counter-insurgency. Would the hon. Minister enlighten us as to what is this modernisation that he has in mind when he replied to this question?

SHRI HARIN PATHAK: Sir, as far as modernisation of police forces and Paramilitary Forces is concerned, we have worked out a scheme under which we are giving grants and loans to the State Governments. We are giving enough money.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I am talking about the Parliamentary Forces.

SHRI HARIN PATHAK: We are providing enough money to the Central Forces, if it is required by them.

DR. MANMOHAN SINGH: You should study that book.

Mineral and metal wealth in reserved forest areas and tribal areas

*384. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether reserved forest areas and tribal areas are bestowed with precious mineral and metal wealth; and

(b) if so, the action to explore the top minerals from those areas ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Survey by Geological Survey of India suggests that forest and tribal areas in India have mineral potential. The National Mineral Policy, 1993, *inter alia* recognizes that the policies governing the mining and